स्थापना दिवस संबोधन

श्री राधा मोहन सिंह

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री

भाकृअनुप का 90वां स्थापना दिवस

16 जुलाई, 2018

नई दिल्ली

मंच पर विराजमान मेरे सहयोगी माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्रीमान् गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ; श्रीमान् परशोत्तम रूपाला जी ; श्रीमती कृष्णा राज जी; डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर; डेयर के विशेष सचिव श्री सी. राऊल; वित्तीय सलाहकार श्री प्रधान; यहां उपस्थित वैज्ञानिक एवं छात्र; मीडिया बंधु; किसान भाइयों; देवियो व सज्जनों।

1. सर्वप्रथम मैं हरित क्रान्ति के अगुआ और देश की कृषि बेहतरी में अपना उल्लेखनीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 90वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिकों, किसानों व मीडिया बंधुओं को मैं बधाई देता हूं। 90 साल का कालखण्ड काफी बड़ा होता है और मुझे खुशी है कि सन् 1929 में स्थापित आईसीएआर ने अपनी स्थापना को सही साबित करते हुए न केवल हमारे देश को आयातक राष्ट्र से एक निर्यातक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया वरन् खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता और पोषणिक सुरक्षा दी। हमारे कुशल वैज्ञानिकों के अनुसंधान परिणामों और किसान भाइयों की कड़ी मेहनत से आज हमारे अनाज के भण्डार भरे पड़े हैं और हमारा देश आयातक की भूमिका से आगे बढ़कर एक निर्यातक की भूमिका में आ गया है। इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बधाई ।

2. हमारी सरकार, **सबका साथ - सबका विकास** के मूलमंत्र को ध्यान में रखकर काम कर रही है और पिछले चार सालों में आईसीएआर ने भी इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कृषि अनुसंधान के अग्रणी संस्थान **आईएआरआई, Pusa Institute** की तर्ज पर दिल्ली से बाहर पहली बार आईएआरआई, असम और आईएआरआई, झारखण्ड की स्थापना की। हमारा मानना है कि देश में दूसरी हरित क्रान्ति का प्रादुर्भाव देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भूभाग में होगा और निश्चित रूप से असम और झारखण्ड में आईएआरआई जैसे अग्रणी संस्थान की स्थापना करने से इस कार्य में तेजी आएगी।

3. हमारी सरकार का फोकस **"वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना"** करने पर है। सरकार का पूरा ध्यान किसान कल्याण पर केन्द्रित है। इसका उदाहरण वर्ष 2018 का केन्द्रीय बजट है जो कि पूरी तरह से किसानों और किसानी को समर्पित है जिसमें कृषि क्षेत्र के समग्र विकास पर फोकस किया गया है । इस बार के बजट में पहली बार Rural Outlay में 30% तक बढ़ोतरी की गई है। पिछली सरकारों के दौरान मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला खर्च अधिकतम बजटीय प्रावधानों से कम रहता था। जहां वर्ष 2009-14 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुल रूपये 1,21,082 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था जबकि इसके मुकाबले में वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014-19 में कुल रूपये 2,11,694 करोड़ आवंटित किए गए जो कि 74.5 प्रतिशत की

उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 12 प्रतिशत है जबकि लगभग 58 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि पर आश्रित है। अगर यही रूझान बना रहा तब वर्ष 2026 तक जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत तक आने की संभावना है लेकिन फिर भी इसमें 37 प्रतिशत जनसंख्या की निर्भरता बनी रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में कृषि का महत्व लोगों की आजीविका के संबंध में हमेशा रहा है और भविष्य में भी बना रहेगा और इसीलिए हमें कृषि पर लगातार विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

4. मुझे खुशी है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आईसीएआर द्वारा राज्य वार समन्वय समितियां (Statewise Coordination Committees) बनाई गई हैं। इन कमेटियों में राज्यों के कृषि विशेषज्ञों को शामिल किया गया । काम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए इन कमेटियों ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। मुझे विश्वास है कि इन रिपोर्ट के आधार पर किसानों की आय को किस प्रकार बढ़ाया जाए, इस दिशा में आईसीएआर एवं संबंधित राज्यों द्वारा कार्य करने में तेजी लाई जाएगी।
5. हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले यानि बुवाई से पहले और बुवाई के बाद और फसल कटाई के बाद भी। फसलों के तैयार होने से लेकर उसकी बिक्री तक, बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मददगार हो सकती है, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। बुवाई से पहले किसान भाई यह जान पाएं कि उनके खेत की मिट्टी कैसी है, उसकी हैल्थ कैसी है, उस पर किस प्रकार की फसल उगानी चाहिए, इसके लिए Soil Health Card शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि Soil Health Card योजना को फरवरी, 2015 में प्रारंभ किया गया था और अभी तक किसानों को 14.20 करोड़ सॉयल हैल्थ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं।
6. **हर खेत को पानी मिले - माननीय प्रधानमंत्री जी** के इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज देशभर में लगभग 100 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। उत्पादन को बढ़ाने में आईसीएआर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसान को तब होती है जब उसका उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उत्पादन बढ़े और किसान की जेब भरे, इसके लिए Online Plateform e-NAM शुरू किया गया ताकि किसानों को उनकी उपज का सही और पूरा पैसा मिल सके। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिलें, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बड़ा फैसला किया । तय किया गया है कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी फसल लागत का कम से कम डेढ़ गुना घोषित किया जाएगा। और इस फैसले को लागू करने की दिशा में 23 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुना बढ़ोतरी भी कर दी गई है।

7. कृषि उत्पादन को बढ़ाने में उन्नत किस्मों, तकनीकों और बीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्ष 2010-2014 की चार साल की अवधि में जहां 448 किस्में खेती के लिए जारी की गईं थीं वहीं वर्ष 2014-2018 की चार साल की अवधि में 795 उन्नत किस्मों को खेती के लिए जारी किया गया जो कि लगभग दोगुनी संख्या में हैं। प्रजनक बीजों के मामले में वर्ष 2013-14 में जहां मांग व उत्पादन क्रमश: 8479 टन एवं 8927 टन रहा वहीं 2016-17 में यह आंकड़ा क्रमश: 10405 टन एवं 12265 टन तक पहुंच गया। किसी भी उन्नत किस्म को तैयार करने और उसे खेती के लिए जारी करने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसमें वैज्ञानिकों की तपस्या एवं धैर्य शामिल होता है। इसलिए उन्नत किस्मों को दोगुनी संख्या में विकसित करने के लिए आप सभी को बधाई।
8. कृषि उत्पादन को बढ़ाने में आईसीएआर द्वारा विकसित तकनीकों और हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि पिछले चार साल में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस वर्ष खाद्यान्न उत्पादन 275.68 मिलियन टन हुआ है जो कि वर्ष 2013-14 में हासिल उत्पादन (265.04 मिलियन टन) के मुकाबले में लगभग 10.64 मिलियन टन ज्यादा है। बागवानी फसलें जिनका पोषणिक सुरक्षा में अहम योगदान है, का इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जो कि 300 के आंकडे को पार करके 305 मिलियन टन हो गया है। बागवानी उत्पादन के मामले में आज भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। दाल उत्पादन के मामले में पहले स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बाजार में दालों के दाम ज्यादा थे, हमने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और देशभर में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाने के लिए 150 सीड हब बनाये गए और दलहनी फसलों के अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन किए गए। आज दालों का 22 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है जो कि आत्म निर्भरता के काफी नजदीक है।
9. हमें Lab to Land कार्यक्रम को और मजबूती प्रदान करनी है और इस दिशा में आईसीएआर के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है। किसानों की सीधी और पहली पहुंच कृषि विज्ञान केन्द्र तक होती है, उन्नत तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए ये प्रवेश द्वार हैं। किसानों को उन्नत तकनीक उनके घर-द्वार के नजदीक मिले, उसका सजीव प्रदर्शन उसे देखने को मिले, ताकि उसमें विश्वास पैदा हो, इसके लिए पिछले चार सालों में कृषि विज्ञान केन्द्रों को मजबूती प्रदान की गई है, इसके लिए कैबिनेट द्वारा 12वीं योजना में 3900 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता अनुमोदित की गई। 11वीं योजना तक जहां कृषि विज्ञान केन्द्रों की संख्या 630 थी वहीं इनमें अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए इनकी संख्या को बढ़ाकर 692 किया गया है। उन्नत तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए **मेरा गांव - मेरा गौरव** कार्यक्रम प्रारंभ किया गया

जिसमें 4-5 वैज्ञानिकों की टीम अपने आसपास के गांवों को अंगीकृत करके वहां नियमित दौरे करती हैं, किसानों के साथ सम्पर्क में रहती है, उन्हें जरूरी वैज्ञानिक व तकनीकी सलाह देती है। मुझे खुशी है कि अभी तक इस योजना के तहत 13,500 गांवों को अंगीकृत किया जा चुका है।

10. वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती कहीं ज्यादा है और साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन पर United Nations Framework Convention 2015 Paris Agreement के अंतर्गत 195 देशों ने ग्लोबल औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि सीमित करने के लिए कार्रवाई करने में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। ग्रीनहाउस इमीशन में कृषि की बड़ी भागीदारी है। मुझे खुशी है कि आईसीएआर द्वारा छोटे व सीमान्त किसानों और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को शामिल करते हुए कुल 45 Integrated Farming System Models तैयार किए गए हैं। इसी दिशा में आईसीएआर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से 29 राज्यों में जलवायु अनुकूल तकनीकों को प्रदर्शित किया जा रहा है और उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

11. मुझे खुशी है कि गणतंत्र दिवस समारोह में पहली बार आईसीएआर की झांकी को शामिल किया गया। **"मिश्रित खेती - खुशियों की खेती"** स्लोगन से सजी इस झांकी ने पूरे देश का और विशेषकर किसान भाइयों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इसके लिए आईसीएआर बधाई का पात्र है। आईसीएआर द्वारा बासमती चावल की पूसा बासमती 1121 किस्म विकसित की गई है जिसकी सुगन्ध दुनियाभर में फैल रही है और इससे भारत को प्रति वर्ष 20 हजार करोड़ से भी अधिक की विदेशी मुद्रा मिल रही है। वर्ष 2011-14 में जहां इसके निर्यात से 62,800 करोड़ रूपये मिलते थे वहीं वर्ष 2014-18 के चार सालों में इसके निर्यात से 71,900 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है जो कि वर्ष 2011-14 की तुलना में पिछले चार साल 2014-18 में 9,100 करोड़ रूपये अधिक है।

12. अभी हाल ही में एग्रीकल्चर में पराली जलाने के कारण पर्यावरण की समस्या देखने में आ रही है। मुझे खुशी है कि इस दिशा में कृषि के इस महत्वपूर्ण अपशिष्ट को बचाने के लिए मशीनें खरीदने में किसानों को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग केन्द्रों को 80 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय किया गया है। इस दिशा में पहल करते हुए आईसीएआर के 35 कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। 45,000 किसानों में जागरूकता उत्पन्न की गई, अपशिष्ट

प्रबंधन क्रियाओं पर 4,708 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,200 Live Demonstration लगाये गये। निश्चित रूप से इससे पराली को जलाने में कमी आएगी और इसका उपयोग खेती में उर्वरता को बढ़ाने में किया जा सकेगा।

13. आने वाला समय टैक्नोलॉजी संचालित होगा और कृषि क्षेत्र इससे वंचित नहीं रह सकेगा । एग्रीकल्चर में जितना जल्दी हम माडर्न टैक्नोलॉजी को अपनायेंगे, कृषि की बेहतरी भी उसी तेजी से होगी। नैनो फर्टिलाइजर का उपयोग करने से कम मात्रा में भी इनका प्रयोग करने पर अधिक लाभ होगा, नैनो टैक्नोलॉजी का उपयोग खाद्य एवं कृषि में किया जा सकता है। एग्री- रोबोटिक्स से प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में किसानों की मेहनत को कम करने में मदद मिलेगी। Floating Horticulture, Rooftop खेती, वर्टिकल फार्मिंग, Agriculture Drone ऐसे विषय हैं जिन पर और अधिक तेजी से कार्य करने की जरूरत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), हर क्षेत्र में टैक्नोलॉजी के विकास में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और कृषि में इसका उपयोग हमें करना चाहिए। खेती का भविष्य प्रति बूंद - अधिक फसल (per drop - more crop), उर्वरकों का कम से कम प्रयोग तथा कीटनाशकों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करने वाली Hydroponics & Aeroponics Systems का है। भारत में साल में अधिकांश समय अच्छी धूप बनी रहती है, खेती बाड़ी में इसका लाभ उठाने के लिए आईसीएआर द्वारा Agri - photo Voltaic System का विकास किया गया है जिसमें खेती, बिजली उत्पादन और वॉटर हार्वेस्टिंग शामिल है। हमें कृषि में ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना है और इसके लिए नई तकनीकें लानी हैं।

14. देश के युवा अधिक से अधिक कृषि की ओर आकर्षित हों, उससे जुड़ें, इसके लिए कृषि शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की जरूरत है। इस दिशा में स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम में छात्रों के कौशल विकास को अब पूरे एक साल के लिए शामिल किया गया है ताकि छात्र कहीं अधिक अनुभव हासिल कर कृषि उद्यमी बनें और अन्य को भी रोजगार मुहैया करा सकें। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए कृषि शिक्षा को प्रोफेशनल डिग्री घोषित किया गया है। इससे छात्रों को विदेशों में रोजगार पाने और हायर एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर "Agri services & Business by Harnessing Youth through Agricultural Skills (अभ्यास)" एक वर्षीय डिप्लोमा प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसमें हमारे नवयुवक कृषि की जानकारी प्राप्त कर पायेंगे और इससे उन्हें नौकरी पाने अथवा अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

15. कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना जरूरी है। हमारी टैक्नोलॉजी और निजी क्षेत्र का इनवेस्टमेन्ट मिलकर कृषि विकास की बुनियाद तैयार करेगा। किसानों को कृषि उद्यमी बनाने की दिशा में आईसीएआर द्वारा 100 से भी अधिक एग्री स्टार्ट-अप को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। मुझे आशा है कि आगे चलकर ये एग्री स्टार्ट अप कृषि उद्यम में अपना वर्चस्व कायम करेंगे।

16. हमें अतीत की सफलताओं पर इतराने की बजाय वर्तमान एवं भावी विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है, हमें आत्ममुग्ध अथवा आत्मसंतुष्ट बनकर नहीं रहना है। हमें भविष्य की ओर देखना है और किसानों और किसानी की बेहतरी की दिशा में लगातार प्रयास करना है। हमारा संकल्प वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है, हम सभी को इसी दिशा में अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत है और विशेषकर आईसीएआर की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, 90 साल तक कृषि का फोकस अधिक से अधिक उत्पादन करने, देश को आयातक से निर्यातक की भूमिका में लाने, भुखमरी का निवारण करने पर था। अब हमें इससे आगे बढ़कर उत्पादकता को बढ़ाने, पौष्टिकता को बढ़ाने, खेती में अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, जलवायु अनुकूल कृषि को प्रोत्साहित करने, खेती बाड़ी के प्रति युवाओं को आकर्षित करने और अंतत: किसानों की आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना है। मुझे वैज्ञानिकों के शोध प्रयासों और अपने किसान भाइयों की मेहनत पर पूरा भरोसा है और आशा है कि हम पहले से भी कहीं अधिक तेजी से कृषि विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे।

धन्यवाद,

जय हिन्द